श्री मंगुभाई पटेल

राज्यपाल, मध्यप्रदेश

का

अभिभाषण

मध्यप्रदेश विधान सभा अधिवेशन

12, माघ–फाल्गुन, 1945 शक भोपाल, बुधवार, 07 फरवरी, 2024

माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सदस्यगण,

1. सभी सम्माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत।
2. सोलहवीं विधानसभा के वर्तमान सत्र में सदन को सम्बोधित करते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि आजादी के अमृतकाल में भारतीय स्वातंत्र्य एवं भारतीय गणतंत्र दोनों के अमृत महोत्सव का साक्षी बनने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। मैं देश की स्वाधीनता और सम्प्रभुता के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले क्रांतिकारियों, महापुरुषों और जननायकों को शत-शत प्रणाम करता हूँ। मध्यप्रदेश विधानसभा की समृद्ध परंपराओं और सशक्त कार्यप्रणाली ने संसदीय लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत बनाया है। यदि भारत लोकतंत्र की माता है तो यह सदन लोकतंत्र का मंदिर।
3. अयोध्या में भगवान श्रीराम की मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा के भव्य समारोह ने भारत ही नहीं, पूरे

विश्व को श्रद्धा, भक्ति और आस्था से सराबोर कर दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में रामराज्य की परिकल्पना और विकसित भारत की संकल्पना, दोनों को साकार होते देखना निश्चय ही एक अद्‌भुत-अभूतपूर्व-अविस्मरणीय अनुभव है। चित्रकूट एवं ओरछा सहित प्रदेश की सीमाओं में सम्पूर्ण राम वन गमन पथ के सर्वांगीण विकास के लिए मेरी सरकार ने प्रतिबद्ध होकर कार्य प्रारंभ कर दिया है। प्रदेश भर में जहाँ-जहाँ भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण के चरण पड़े, उन स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा। भारत की भूमि पर शूरवीरों की एक महान परम्परा रही है। मेरी सरकार ने शूरवीरों के जीवन एवं बलिदान के प्रति आदरांजलि एवं भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्वरूप वीर भारत संग्रहालय की स्थापना का निर्णय लिया है।

4. भारत की अर्थव्यवस्था पर हाल ही में जारी रिपोर्ट विगत लगभग 10 वर्ष में आर्थिक प्रगति और सामाजिक उत्थान की नई ऊँचाइयों को छूने में मिली अपार सफलता की कहानी बयाँ करती है। जहाँ दुनिया की बड़ी अर्थ व्यवस्थाएँ 3% से अधिक की विकास दर पाने के लिए भी संघर्ष कर रही हैं, वहीं भारत की विकास दर लगातार 3 वर्षों से 7% से अधिक बनी हुई है। आज देश की 78% से अधिक महिलाओं के पास अपना बैंक अकाउंट है। देश के श्रम बल में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर 37% हो गई है। बेटियों का उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 4 गुना से भी अधिक और हायर सेकेण्डरी शिक्षा में 2 गुना से भी अधिक बढ़ गया है। जन-कल्याण की अवधारणा अब जन-सशक्तिकरण का रूप ले चुकी है।

5. वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट अमृत-काल का बजट है। यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में देश को आगे बढ़ाने वाला बजट है। ये अंतरिम बजट दूरदर्शी, सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी है। सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों के विकास और कल्याण पर इसमें फोकस किया गया है। ये सबका साथ-सबका विकास-सबका प्रयास और सबका विश्वास के मूल मंत्र को सार्थक करने वाला है। विकास के लिए फिजिकल, डिजिटल और सोशल-तीनों प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाने का संकल्प बजट में किया गया है। यह गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं, सभी को सशक्त बनाने वाला बजट है।

6. ये नए भारत का समय है, ये विश्व-मित्र भारत का समय है, ये अमृत-पीढ़ी की ऊर्जा से प्रगति के नए प्रतिमान रचने का समय है, ये प्रधानमंत्री

श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण का समय है, ये इक्कीसवीं सदी के हर क्षेत्र में अग्रणी मध्यप्रदेश को गढ़ने का समय है। मेरी सरकार एक ऐसी डबल इंजन सरकार है, जो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के चौतरफा विकास और जन-जन के कल्याण के लिए नीतियाँ बना रही है, निर्णय ले रही है और सुराज के सपने सच करके दिखा रही है।

7. मध्यप्रदेश में विकसित भारत संकल्प-यात्रा, माननीय प्रधानमंत्री जी के वर्ष-2047 तक विकसित भारत के निर्माण की प्रबल अभिव्यक्ति बनकर उभरी है। यात्रा के दौरान केन्द्र और राज्य की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर्गत 50 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया है। मेरी सरकार ने संकल्प-पत्र-2023 में प्रदेश की जनता के कल्याण के संकल्पों पर तेज गति से कार्य प्रारंभ

कर दिया है, जिसके चलते विकास की परिकल्पनाएँ सुखद परिणामों में परिवर्तित होने लगी हैं।

8. मेरी सरकार के प्रयासों से अधोसंरचनात्मक पूँजीगत कार्यों पर अधिक से अधिक व्यय कर अर्थव्यवस्था को तेज गति से विकसित किया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में 56 हजार 256 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड पूँजीगत व्यय का लक्ष्य है।

9. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और निर्णय-कौशल की बदौलत केन-बेतवा परियोजना की भाँति पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना की स्वीकृति प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। लगभग 35 हजार करोड़ रुपए की लागत की इस परियोजना से प्रदेश के 10 जिलों-शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, गुना, शाजापुर, उज्जैन, इंदौर और देवास को

पेयजल एवं 3 लाख 37 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। संकल्प-पत्र 2023 के संकल्प को पूरा करने के लिए नर्मदा कछार की 1 लाख 12 हजार हेक्टेयर से अधिक की सिंचाई क्षमता की 3 परियोजनाओं के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है।

10. भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश को 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक लागत की 724 किलोमीटर लंबी 24 सड़क परियोजनाओं की सौगात मिली है। इन परियोजनाओं से न केवल उद्योग और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पर्यटन स्थलों और तीर्थ स्थलों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी एवं सीमावर्ती राज्यों के बीच यातायात सुगम हो सकेगा। मेरी सरकार के प्रयासों से इस वर्ष अब तक 3 हजार किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कों का

सुदृढ़ीकरण एवं 4 हजार किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कों का नवीनीकरण हो चुका है।

11. मेरी सरकार घरेलू, औद्योगिक एवं गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे विद्युत प्रदाय सुनिश्चित कर रही है। आगामी वित्तीय वर्ष में विद्युत क्षमता में 5 हजार मेगावॉट से अधिक की बढ़ोत्तरी का लक्ष्य है। मेरी सरकार के प्रयासों से नवकरणीय ऊर्जा क्षमता में विगत 11 वर्षों में लगभग 11 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। नवकरणीय ऊर्जा आपूर्ति और सौर ऊर्जा क्षमता में मध्यप्रदेश, देश के टॉप-टेन राज्यों में शामिल है। ओंकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग परियोजना का कार्य प्रारंभ करने के साथ-साथ बिरसिंहपुर, इंदिरा सागर एवं गांधी सागर जलाशयों में फ्लोटिंग सोलर परियोजना विकास हेतु तकनीकी सर्वे कार्य किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत प्रदेश में 75 हजार सोलर रूफटॉप स्थापना का लक्ष्य है।

12. लोक परिसंपत्ति प्रबंधन जिला प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वर्तमान एवं विगत वित्तीय वर्ष मिलाकर 17 जिलों को आधारभूत संरचना विकास हेतु 126 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई गई है।

13. मेरी सरकार गरीबों के कल्याण और उत्थान की चिंता करने वाली सरकार है। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विगत 9 वर्षों में मध्यप्रदेश के 2 करोड़ 30 लाख लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। बड़ी आबादी को बहुआयामी गरीबी से उबारने वाले राज्यों में मध्यप्रदेश, देश में तीसरे स्थान पर है।

14. इंदौर स्थित हुकुमचंद मिल के 4 हजार 800 श्रमिक परिवारों को उनके हक की राशि 224 करोड़ रुपए के भुगतान की पहल कर लंबे

समय से संघर्ष कर रहे मजदूरों को यदि किसी ने न्याय दिलाया है तो वह माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मेरी सरकार ने दिलाया है। प्रदेश की अन्य मिलों में भी ऐसे प्रकरणों में मजदूरों के हित, मजदूरों को समर्पित करने के लिए सरकार हर संभव उपाय करेगी। तेंदूपत्ता संग्राहकों का मानदेय 3 हजार रुपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4 हजार रुपए कर मेरी सरकार ने संकल्प-पत्र में दी गई गारंटी को पूरा किया है।

15. संबल योजना के अंतर्गत 5 लाख 25 हजार से अधिक हितग्राहियों को लगभग 5 हजार करोड़ रुपए की राशि हितलाभ के रूप में वितरित की गई है। जल जीवन मिशन अंतर्गत अब तक प्रदेश के 12 हजार से अधिक ग्रामों के शत-प्रतिशत घरों में नल से जल पहुँचाया जा चुका है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से हर पात्र गरीब परिवार के अपने घर का सपना सच हो रहा है। पीएम स्वनिधि योजना में 140% उपलब्धि अर्जित कर मध्यप्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है। दिव्यांगजन कल्याण के लिए उत्कृष्ट कार्य हेतु मध्यप्रदेश को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगले वित्तीय वर्ष में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के माध्यम से लगभग 60 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

16. मेरी सरकार कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए सदैव ही संवेदनशील रही है। प्रदेश के 2 हजार 600 से अधिक छात्रावासों एवं आश्रमों में अध्ययनरत जनजातीय वर्ग के छात्र-छात्राओं को इस वर्ष अब तक नि:शुल्क सुविधाओं तथा शिष्यवृत्ति के रूप में 325 करोड़ रुपए से अधिक और छात्रवृत्ति के रूप में 102 करोड़

रुपए से अधिक की राशि का भुगतान किया गया है। प्रधानमंत्री आदि-आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत प्रदेश के 2 हजार 500 से अधिक ग्रामों के विकास हेतु लगभग 400 करोड़ रुपए की राशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश के जनजातीय भाई-बहनों के आर्थिक उन्नयन के लिए परंपरागत कौशल का उपयोग करते हुए हेरिटेज मदिरा निर्माण के अधिकार दिए गए हैं। जाति प्रमाण-पत्र प्रदाय अभियान के तहत लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से प्रदेशभर के स्कूली छात्र-छात्राओं को अब तक लगभग 1 करोड़ 39 लाख से अधिक डिजिटल हस्ताक्षरित रंगीन प्रमाण-पत्र प्रदान किए जा चुके हैं।

17. संत शिरोमणि पूज्य रविदास जी की पावन स्मृति में प्रदेश के 30 अनुसूचित जाति बाहुल्य जिलों में संत रविदास स्मारक-सह-सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री कौशल

उन्नयन प्रशिक्षण योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति के लगभग 5 हजार युवाओं को प्रशिक्षण देकर 3 हजार से अधिक युवाओं को विभिन्न संस्थानों में रोज़गार उपलब्ध कराया गया है। संत रविदास स्व-रोज़गार योजनान्तर्गत 34 करोड़ से अधिक एवं डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत 3 करोड़ से अधिक स्व-रोज़गार ऋण सहायता वितरित की गई है।

18. मेरी सरकार ने पीएम जन-मन योजना अंतर्गत प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल जिलों में 7 हजार 300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से आँगनवाड़ी केन्द्रों, छात्रावासों, बहुउद्देशीय केंद्रों, सड़कों, पुलों और आवासों के निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। योजना अंतर्गत 23 जिलों की 4 हजार 597 बसाहटों में निवास करने वाले बैगा, सहरिया एवं भारिया जनजाति

के 11 लाख से अधिक भाई-बहन लाभान्वित होंगे।

19. पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग हेतु संचालित मुख्यमंत्री उद्यम एवं स्व-रोज़गार योजनांतर्गत इस वर्ष अब तक 280 से अधिक हितग्राहियों को 15 करोड़ रुपए से अधिक की कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराई गई है। पिछड़ा वर्ग के युवक-युवतियों को विदेश में रोज़गार उपलब्ध कराने की योजनांतर्गत इस वर्ष 45 युवाओं को कन्स्ट्रक्शन सेक्टर एवं 15 युवतियों को केयर वर्कर जॉब रोल के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु समुदायों के विद्यार्थियों के लिए 29 जिलों में 140 छात्रावास, आश्रम एवं सामुदयिक कल्याण केन्द्रों के माध्यम से नि:शुल्क भोजन एवं आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

20. मेरी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को प्राथमिक कृषि साख संस्थाओं के माध्यम से शून्य % ब्याज दर पर राशि 3 लाख रुपए तक की ऋण सीमा तक अल्पावधि कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। सहकारी समितियों द्वारा इस वर्ष अब तक लगभग 17 हजार 500 करोड़ रुपए का अल्पावधि ऋण वितरण किया गया है। मेरी सरकार प्रदेश के दूध उत्पादकों और डेयरी किसानों की समृद्धि के लिए मध्यप्रदेश दुग्ध महासंघ के माध्यम से विभिन्न राज्यों के डेयरी फेडरेशन्स के साथ समन्वय और सहभागिता करते हुए साँची ब्रांड को नई ऊँचाइयों पर ले जाने के लिए संकल्पित है।

21. प्रदेश के 4 लाख 51 हजार से अधिक पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किए गए हैं। चलित पशु चिकित्सा इकाइयों के

माध्यम से 4 लाख 71 हजार से अधिक पशुपालकों को घर पहुँच चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। अब तक 87 हजार से अधिक मछुआ क्रेडिट कार्ड स्वीकृत कर मध्यप्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है।

22. संकल्प-पत्र-2023 की गारंटी को पूरा करते हुए मेरी सरकार ने कोदो-कुटकी जैसे मिलेट्स उगाने वाले कृषकों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में 3 वर्षों हेतु 105 करोड़ रुपए से अधिक की 'रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना' लागू की गई है। प्रदेश के लिए यह निश्चय ही गौरव का विषय है कि डिण्डौरी जिले की सुश्री लहरीबाई पडिया को श्रीअन्न की खेती तथा दुर्लभ श्रीअन्न बीजों के संरक्षण हेतु 'प्लांट जीनोम सेवियर फार्मर पुरस्कार' से सम्मानित किया गया है।

23. प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर विपणन वर्ष 2023-24 में 1 लाख 75 हजार से अधिक कृषकों से 5 लाख 62 हजार मीट्रिक टन से अधिक मूँग की खरीदी गई है। मूँग की उपार्जित मात्रा का मूल्य 4 हजार 363 करोड़ रुपए से भी अधिक है, जो कि एक रिकॉर्ड है।

24. उद्यानिकी फसलों के प्रोत्साहन हेतु इस वर्ष लगभग 4 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता उपलब्ध कराकर 1 हजार 800 से अधिक कृषकों को लाभान्वित किया गया है। नर्सरियों के कुशल प्रबंधन हेतु मध्यप्रदेश का प्रथम अत्याधुनिक नर्सरी पोर्टल तैयार किया गया है, जिसपर अब तक 300 नर्सरियों को लिंक किया जा चुका है। उद्यानिकी उत्पादों जैसे बालम खीरा, धनिया, जीरावन, केला, खुरसानी इमली, खुरचन, अचारी आम, मटर, गराडू, मालवी आलू, गाजरिया आम, सीताफल, गुड़, बरमान

बैंगन और सिंघाड़ा आदि को प्रदेश की वैश्विक पहचान बनाने के लिए चिन्हित किया गया है।

25. मेरी सरकार ने महिला सशक्तिकरण को अपना मिशन बनाया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत 3 चरणों में अब तक 85 लाख से अधिक नि:शुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। इस माह पात्र बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर के लिए उनके 45 लाख 89 हजार गैस सिलेंडर रीफिल पर 118 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण कर संकल्प-पत्र में दी गई गारंटी को पूरा किया गया है। मकर संक्रांति उत्सव के दौरान पात्र लाड़ली बहनों के खातों में 1 हजार 576 करोड़ रुपए से अधिक की राशि और 56 लाख से अधिक पात्र हितग्राहियों के खातों में 341 करोड़ रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि अंतरित की गई है। इस अवसर पर महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु रोज़गार मेलों

एवं परंपरागत खेलों जैसी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। आहार अनुदान योजना अंतर्गत 240 करोड़ रुपए व्यय किया जाकर 2 लाख से अधिक पात्र महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है।

26. मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना अंतर्गत अब तक 14 लाख से अधिक बालिकाओं को 388 करोड़ रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति का वितरण किया जा चुका है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश, राष्ट्रीय स्तर पर पाँच वर्षों से निरंतर प्रथम स्थान पर है। मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्द्धन कार्यक्रम अंतर्गत पंजीकृत बच्चों में से 88% से अधिक बच्चों के पोषण स्तर को सामान्य स्तर पर लाया गया है। महिलाओं के लिए नि:शुल्क ड्रायविंग लाइसेंस की योजना के माध्यम से 7 लाख 39 हजार से अधिक लर्निंग लाइसेंस तथा 6 लाख

25 हजार से अधिक ड्रायविंग लाइसेंस जारी किए गए हैं। राज्य सरकार ने रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई एवं अन्य वीरांगनाओं की जीवनी को सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने का भी निर्णय लिया है।

27. माननीय प्रधानमंत्री जी ने 21वीं सदी के नए भारत के निर्माण में युवाओं की भागीदारी के लिए 'मेरा युवा भारत संगठन' की नींव रखी है। मेरी सरकार भी प्रदेश की युवा-शक्ति के चेहरों पर मुस्कान और सपनों की उड़ान को नई गति और नई ऊर्जा दे रही है। मुरैना में आयोजित रोज़गार दिवस के अवसर पर रिकॉर्ड 7 लाख युवाओं को 5 हजार करोड़ के स्व-रोज़गार ऋण वितरित किए गए हैं। जिसके माध्यम से प्रदेश में बड़ी संख्या में रोज़गार सृजन हुआ है। जो प्रदेश के इतिहास में 1 दिन में स्व-रोज़गार के लिए दी गई अब तक की सबसे बड़ी ऋण

सहायता है। लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित लगभग 700 उम्मीदवारों को शासकीय सेवा के नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। प्रत्येक जिले में निजी क्षेत्र में रोज़गार उपलब्ध कराने हेतु इस वर्ष अब तक 423 रोज़गार मेलों का आयोजन कर लगभग 40 हजार आवेदकों को ऑफर लेटर विभिन्न नियोजकों द्वारा प्रदाय किए गए हैं।

28. मेरी सरकार ने मध्यप्रदेश के युवाओं को गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा प्रदान करने के संकल्प की पूर्ति के लिए दिन-रात एक किया है, और उसी का परिणाम है कि वर्ष 2021-22 के लिए सकल नामांकन अनुपात में प्रदेश के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय सकल नामांकन अनुपात 28.4 से आगे निकलकर 28.9 तक पहुँच गया है। मेरी सरकार ने 55 जिलों में कुल 55 शासकीय महाविद्यालयों का पीएम उत्कृष्टता

महाविद्यालय के रूप में उन्नयन करने, सागर में रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय, खरगोन जिले में क्रांतिसूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय एवं गुना जिले में भी एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना करने का निर्णय लिया है।

29. विश्वविद्यालयों में छात्र-छात्राओं की अंकसूची एवं उपाधियों को डिजीलॉकर में अपलोड करने की व्यवस्था लागू की जा रही है। राज्य नीति आयोग में युवा शोध दल कार्यरत हैं जो विभिन्न ज्ञान एवं शोध-आधारित गतिविधियों में संलग्न हैं। यह युवाओं द्वारा राज्य में नीति निर्माण एवं विकास के कार्यों में की जा रही भागीदारी का अनूठा उदाहरण है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मिशन लाइफ अंतर्गत यूथ फॉर लाइफ कार्यक्रम में कुल 2 हजार से अधिक युवा लाइफ वॉलेंटियर्स को प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य है।

30. लगभग 23 वर्ष बाद यह सौभाग्यशाली अवसर आया है, जब एक साथ मध्यप्रदेश के 3 खिलाड़ियों को अर्जुन अवॉर्ड एवं 1 प्रशिक्षक को द्रोणाचार्य अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। 37 वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के 416 खिलाड़ियों द्वारा 37 खेलों में भाग लेकर 112 पदक प्राप्त करते हुए अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। प्रदेश में मलखम्ब एवं जिम्नास्टिक अकादमी की स्थापना करने का लक्ष्य है।

31. मेरी सरकार द्वारा युवाओं के कौशल विकास एवं रोज़गार पर फोकस करते हुए महाविद्यालयों में बाजार की जरूरतों के आधार पर सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ किए गए। प्रदेश में 4 नए ग्लोबल स्किल्स पार्क विकसित किए जा रहे हैं। इस वर्ष 22 नवीन आईटीआई की स्वीकृति उपरांत प्रदेश में शासकीय आईटीआई की संख्या बढ़कर 290 हो गई है।

मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना अंतर्गत अब तक 20 हजार 500 से अधिक अनुबंध किए जा चुके हैं।

32. आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से फ्यूचर जॉब स्किल कोर्सेज में 7 हजार युवाओं को प्रशिक्षण दिलाए जाने की योजना है। राज्य के इंजीनियरिंग महाविद्यालय जबलपुर में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंजीनियरिंग महाविद्यालय उज्जैन में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एवं सरदार वल्लभ भाई पॉलीटेक्निक भोपाल में कम्प्यूटर विजन के क्षेत्र में 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' स्थापित किए जाने का लक्ष्य है। यह निश्चय ही हर्ष का विषय है कि आईआईटी इंदौर द्वारा देश में शोध-आधारित प्रथम आईआईटी डीप-टेक रिसर्च और डिस्कवरी कैंपस की स्थापना उज्जैन में की जा रही है। लगभग 474 करोड़ रुपए की लागत से

स्थापित होने वाला यह देश का अपनी तरह का यह अनूठा संस्थान होगा, जो भविष्य की प्रौद्योगिकी में विश्व-स्तरीय अनुसंधान केंद्र बनेगा।

33. संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास यदि साध्य है तो शिक्षा उसका सबसे बड़ा साधन। प्रदेश में अब तक 369 सीएम राइज़ विद्यालयों का संचालन प्रारंभ हो चुका है। प्रदेश में 313 विकासखण्डों में कुल 730 स्कूलों को पीएमश्री स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रथम चरण में 416 विद्यालयों को इस योजना के तहत चयनित किया गया है। इन स्कूलों को ग्रीन स्कूल की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में लगभग 92 लाख पात्र छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं। निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना अंतर्गत 4 लाख 70 हजार विद्यार्थियों को 182

करोड़ रुपए की राशि प्रदाय की जा चुकी है। मेधावी छात्र-छात्राओं को मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना अंतर्गत वर्ष 2024-25 के लिए राशि 400 करोड़ रुपए की शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा युवाओं को देशभक्ति की ऊर्जा से ओत-प्रोत करने के लिए प्रारंभ की गई अग्निवीर योजना में प्रदेश के युवाओं का अधिक से अधिक चयन हो, इस उद्देश्य से पात्र युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य है।

34. स्वास्थ्य सेवाओं में प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए मेरी सरकार लगभग 20 हजार करोड़ रुपए के निवेश से निरामय इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का प्रभावी क्रियान्वयन कर रही है। प्रदेश में 11 हजार 454 से अधिक आरोग्य मंदिर क्रियाशील हो गए हैं, जिनसे प्रतिदिन लगभग

डेढ़ लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं। आयुष विभाग के अंतर्गत भी नवीन 238 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए जा रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में 345 मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक आरंभ किए गए हैं, जिनमें 1 करोड़ से अधिक नागरिकों को उपचार प्राप्त हुआ है। संजीवनी 108 ऐम्बुलेंस एवं जननी एक्सप्रेस वाहनों से औसतन 9 हजार से अधिक हितग्राहियों को प्रतिदिन नि:शुल्क परिवहन सेवा मिल रही है। विकसित भारत संकल्प-यात्रा के दौरान 26 हजार 234 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया, जिनमें कुल 54 लाख 51 हजार से अधिक हितग्राहियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। भारतीय चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सागर, शहडोल, नर्मदापुरम, धार, झाबुआ, मंडला, बालाघाट, श्योपुर एवं खजुराहो में नए आयुर्वेदिक महाविद्यालय स्थापित करने का

निर्णय लेकर मेरी सरकार यह सुनिश्चित करने जा रही है कि प्रदेश के प्रत्येक संभाग में कम से कम एक आयुर्वेदिक महाविद्यालय हो।

35. प्रदेश में कुल 14 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित हैं और 10 नए महाविद्यालयों की स्थापना के लक्ष्य की पूर्ति होने पर यह संख्या बढ़कर 24 हो जाएगी। मेरी सरकार द्वारा भोपाल गैस त्रासदी प्रभावित क्षेत्रों में 6 बड़े चिकित्सालय एवं 9 डिस्पेन्सरी संचालित की जा रही हैं, जिनके माध्यम से गैस पीड़ितों को निरंतर उपचार का लाभ मिल रहा है।

36. आयुष्मान भारत मिशन के अंतर्गत अब तक 3 करोड़ 86 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर केन्द्र को 104 प्रतिशत क्रियाशील करने पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश को देश में

प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सबसे अधिक लाभार्थियों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य आईडी बनाने के लिए प्रदेश को द्वितीय पुरस्कार और अधिकतम क्षय रोगियों की स्क्रीनिंग के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। शिशु स्वास्थ्य अंतर्गत समस्त 17 संस्थाओं ने क्वालीफाई कर हमने देश में सर्वाधिक मुस्कान प्रमाणित संस्थाओं का कीर्तिमान स्थापित किया है। जन-सुविधा एवं कार्यदक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से चिकित्सा शिक्षा विभाग और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का विलय कर 'लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग' के रूप में पुनर्गठन किया गया है। उज्जैन में देश की पहली हेल्दी एवं हायजीनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम का शुभारंभ हो गया है। मेरी सरकार ने प्रत्येक जिले में जिला अस्पताल एवं सिविल अस्पतालों को एक-एक शव-वाहन उपलब्ध

कराए जाने का निर्णय लिया है। गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रसव की सुविधा को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से मेरी सरकार द्वारा जननी एक्सप्रेस वाहनों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि की जाएगी। देश को सिकल सेल रोग मुक्त बनाने के लिए गठित मिशन की लॉन्चिंग प्रधानमंत्री श्री मोदी ने प्रदेश के शहडोल जिले से की है। वर्ष 2047 के बाद कोई भी बच्चा सिकल सेल रोग के साथ जन्म नहीं ले, मेरी सरकार इस संकल्प को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

37. मेरी सरकार प्रदेश के सभी क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश के माध्यम से चौतरफा विकास को एक नई दिशा दे रही है। जीआईएस आधारित भूमि आवंटन प्रणाली का उपयोग करके निवेशकों को 1 हजार 200 से अधिक औद्योगिक भूखंड आवंटित किए गए हैं। इस सेवा को भारत

सरकार द्वारा देश की सर्वश्रेष्ठ सेवाओं में से एक घोषित किया गया है। दिल्ली-नागपुर इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर के अंतर्गत उद्योगों की स्थापना के लिए सागर जिले में 996 हेक्टेयर, कटनी जिले में 588 हेक्टेयर और सिवनी जिले में 559 भूमि चिन्हित कर ली गई है।

38. औद्योगिक क्षेत्र विक्रम उद्योगपुरी जिला उज्जैन में मेडिकल डिवाइसेस पार्क, मोहासा-बाबई औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत एवं नवकरणीय ऊर्जा के उपकरणों के विनिर्माण क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र सीतापुर में मेगा चमड़ा, फुटवेयर और सहायक सामग्री क्लस्टर तथा धार जिले के भैंसोला में एकीकृत पीएम मित्रा पार्क की स्थापना की परियोजनाएँ मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास का नक्शा बदलकर रख देंगी। निकट भविष्य में प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में रिलायंस कम्प्रेस्ड बॉयोगैस, एशियन पेंट्स, यशोदा लिनेन,

टीवीएस लॉजिस्टिक्स, गोदरेज, जेके टायर आदि औद्योगिक इकाइयों के निवेश से विकास एवं रोज़गार के नए द्वार खुलेंगे।

39. मेरी सरकार द्वारा वर्ष 2024 में नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम ई-बस योजना के अंतर्गत भी प्रदेश को 500 से अधिक बसें प्राप्त होने की संभावना है। ग्वालियर व्यापार मेले में बिकने वाले गैर-परिवहन यानों तथा छोटे परिवहन यानों पर पंजीयन शुल्क एवं रोड टैक्स में 50 प्रतिशत छूट दी गई है। मेरी सरकार आगामी महाशिवरात्रि से गुड़ी-पड़वा के मध्य उज्जैन में विक्रमोत्सव एवं भव्य व्यापार मेले का आयोजन करने जा रही है, जो मध्यप्रदेश के आर्थिक और आध्यात्मिक विकास का प्रतिबिंब बनेगा।

40. भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के

लिए लगभग 400 एकड़ भूमि पर आईटी पार्क विकसित किए गए हैं। इन आईटी पार्कों में 220 इकाइयों को निवेश के लिए कुल 270 भूखण्ड आवंटित किए गए हैं। विश्व के 11 देशों में 'फ्रेंड्स ऑफ एमपी' चैप्टर्स में सक्रिय 15 हजार से अधिक प्रदेशवासी भी प्रदेश के ब्रांड एम्बेसेडर के रूप में कार्य कर रहे हैं।

41. भारत सरकार की 'एक स्टेशन एक उत्पाद' योजनान्तर्गत विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर प्रदेश के कुटीर एवं ग्रामोद्योग उत्पादों का विक्रय प्रारंभ कर दिया गया है। प्रदेश के कृषकों को उनके ककून उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने हेतु 'ककून मार्केट' की स्थापना की गई है, जिसमें इस वर्ष अब तक 35 हजार किलो से अधिक ककून के विक्रय से कृषकों को 1 करोड़ रुपए से अधिक की आय प्राप्त हुई है। मलबरी, टसर, इरी एवं मूँगा के संवर्धन के लिए पचमढ़ी सिल्क

टेक पार्क का शुभारंभ किया गया है, जो कि देश का एकमात्र सिल्क टेक पार्क है।

42. मेरी सरकार प्रदेश के ग्रामों और नगरों के सुनियोजित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार और समाज के सम्मिलित प्रयासों से मध्यप्रदेश, देश का दूसरा सबसे स्वच्छ राज्य, भोपाल देश की स्वच्छतम राजधानी और इंदौर लगातार 7वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है। ये उपलब्धि इस बात की प्रतीक है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से स्वच्छता अब जीवन जीने की संस्कृति में रच-बस गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश को बेस्ट परफार्मिंग स्टेट अवॉर्ड की श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है।

43. स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रारंभ किया गया अमृत सरोवर निर्माण अभियान अब एक नया इतिहास रच चुका है।

प्रदेश में कुल 3 हजार 900 के लक्ष्य के विरुद्ध अभी तक 5 हजार 400 से अधिक सरोवर निर्मित किए जा चुके हैं। देश में सर्वाधिक अमृत सरोवर पूर्ण करने वाले राज्यों में मध्यप्रदेश दूसरे स्थान पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 36 लाख 40 हजार से अधिक आवास पूर्ण कराए जा चुके हैं और इस दृष्टि से मध्यप्रदेश, देश में द्वितीय स्थान पर है।

44. मेरी सरकार ने सुशासन को अपने सर्वोच्च संकल्प का दर्जा दिया है। सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के अनियंत्रित व नियम विरुद्ध प्रयोग एवं बिना लायसेंस के खुले में माँस-मछली आदि के क्रय-विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण किया गया है। यातायात की सुगमता के लिए भोपाल में BRTS को हटाने के सरकार के निर्णय को जनता से सहर्ष समर्थन किया है। मेरी सरकार ने पेंशन प्रकरणों और अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों

के त्वरित निराकरण के लिए जिला स्तर पर विशेष जन-सुनवाई सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया है ।

45. प्रदेश के सभी जिलों में थानों की सीमा व अधिकार क्षेत्र का युक्ति-युक्तकरण किया जा रहा है। गंभीर अपराध के अपराधियों द्वारा जमानत पर छूटकर पुनः अपराध करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए उनकी जमानत निरस्त कराने की कार्यवाही की जा रही है। भारत सरकार द्वारा देश के 10 सर्वश्रेष्ठ थानों में देवास के सिविल लाइन थाने का चयन किया गया है। राष्ट्रीय समारोहों की गरिमा को द्विगुणित करने के लिए प्रत्येक जिले में पुलिस बैण्ड बन रहे हैं।

46. लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत 720 सेवाएँ अधिसूचित की जा चुकी हैं, जिनमें से लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से 341 सेवाएँ ऑनलाइन प्रदाय की जा रही हैं। लोक सेवा गारंटी अंतर्गत

अब तक 9 करोड़ 90 लाख से अधिक आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। स्थानीय चुनौतियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने के लिए संभाग स्तरीय समीक्षा बैठकों का आयोजन किया गया है। नामांतरण, बँटवारा, सीमांकन, नक्शे में तरमीम और राजस्व अभिलेखों की त्रुटियों को सुधारने के लिए प्रदेश में 15 जनवरी से 29 फरवरी, 2024 तक राजस्व महाअभियान चलाया गया है। इस अभियान में अब तक लगभग 1 लाख 50 हजार लंबित प्रकरणों और लगभग 30 हजार नवीन प्रकरणों का निराकरण कर दिया गया है।

47. मेरी सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों में 105 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंडों के लिए डीम्ड स्वीकृति तथा भवन नक्शे के ऑनलाइन अनुमोदन की व्यवस्था लागू की गई है। अब

तक इसके माध्यम से लगभग 2 हजार प्रकरणों में डीम्ड स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। लगभग 4 दशकों बाद पहली बार जनहित एवं जन-सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक इकाइयों की भौगोलिक सीमाओं के युक्ति-युक्तकरण का निर्णय सुशासन की दृष्टि से एक दूरगामी कदम सिद्ध होगा।

48. मेरी सरकार दस्तावेजों के ई-पंजीयन एवं ई-स्टाम्पिंग के लिए संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर को लागू करेगी, जिससे चिन्हित दस्तावेजों का घर बैठे पंजीयन किया जा सकेगा और नागरिक स्वयं ई-स्टाम्प जनरेट कर सकेंगे। डिजिटल भारत की अवधारणा के तहत काष्ठागारों में आनलाइन नीलामी के माध्यम से वनोपज का विक्रय प्रारंभ किया गया है। सरकार ने जेलों के बंदियों की अब तक 3 लाख 10 हजार से अधिक पेशियाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई हैं।

आनन्द एवं खुशहाली विषय पर शोध एवं अध्ययन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से फैलोशिप प्रदान की जा रही है।

49. मेरी सरकार खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन के रोकथाम हेतु नवीन तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस पर आधारित मानव रहित चेकगेट संपूर्ण प्रदेश में स्थापित करने जा रही है। खनिज ब्लाकों की नीलामी में पूरे देश में मध्यप्रदेश का प्रथम स्थान प्राप्त करना, सुशासन के प्रति संकल्पित प्रयासों का ही परिणाम है।

50. मध्यप्रदेश सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और कलात्मक समृद्धि की दृष्टि से भी देश का गौरव है। मेरी सरकार ने वर्ष प्रतिपदा नव सम्वत्सर के शुभारंभ एवं सृष्टि आरंभ दिवस को उज्जैन सहित पूरे प्रदेश में भव्य रूप से मनाने का निर्णय लिया है। इस अवसर पर कलश यात्रा,

विक्रम व्यापार उद्योग मेला, विक्रम वैदिक घड़ी, विक्रम पंचांग के लोकार्पण के साथ सम्राट विक्रमादित्य अलंकरण समारोह भी आयोजित किया जाएगा।

51. वर्ष 2024 के पद्म पुरस्कारों के लिए मध्यप्रदेश की चार विभूतियों श्री भगवतीलाल राजपुरोहित, श्री ओम प्रकाश शर्मा, श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया और श्री कालूराम बामनिया का चयन संपूर्ण प्रदेश के लिए हर्ष और गर्व का विषय है। मध्यप्रदेश संभवतः देश का पहला राज्य है, जहाँ भाषा एवं लुप्त हो रही बोलियों के विकास के लिए अकादमी स्थापित की गई है। प्रदेश में 18 महालोकों के निर्माण के साथ ही शासन संधारित मंदिरों के जीर्णोद्धार को भी प्राथमिकता दी गई है। इस वर्ष जीर्णोद्धार कार्य हेतु अब तक लगभग 12 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है।

52. मेरी सरकार द्वारा वायुयान से प्रयागराज, गंगासागर, शिर्डी एवं मथुरा-वृंदावन की तीर्थ यात्राएँ कराई जाकर अब तक 765 वरिष्ठ नागरिकों को लाभान्वित किया गया है। प्रदेश के 107 प्रमुख तीर्थ एवं 1576 प्रसिद्ध मेले पंजीकृत कर उन्हें विकास कार्यों के लिए अनुदान सहायता दी जा रही है। ग्वालियर में आयोजित ताल-दरबार में प्रदेश के 1300 से अधिक कला साधकों ने वंदे मातरम् की धुन बजाकर गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में प्रदेश का नाम दर्ज कराने की असाधारण उपलब्धि हासिल की है। आगामी सिंहस्थ-2028 कुंभ मेला भव्य, दिव्य और अलौकिक स्वरूप में आयोजित करने के लिए मेरी सरकार ने सुनियोजित रूप से कार्य प्रारंभ कर दिया है। इसके अंतर्गत उज्जैन जिले के साथ-साथ मालवा एवं निमाड़ के समीपवर्ती जिलों में धर्मस्थलों एवं अन्य

अधोसंरचनात्मक विकास का काम भी रोडमैप बनाकर किया जाएगा।

53. मेरी सरकार पर्यटन और संस्कृति के संगम से प्रदेश को देश ही नहीं, दुनिया के आकर्षण का केन्द्र बना रही है। ग्वालियर से बेंगलुरु, अहमदाबाद, दिल्ली और अयोध्या के लिए नई विमान सेवाओं का शुभारंभ किया गया है। रीवा हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है तथा दतिया हवाई पट्टी से उड़ान योजना के अंतर्गत हवाई सेवाएँ संचालित की जायेंगी। केन्द्र सरकार के सहयोग से उज्जैन में अत्याधुनिक एयरपोर्ट की स्थापना करने का लक्ष्य है, जिससे बाबा महाकाल की नगरी में आने वाले श्रद्धालुओं को हवाई यात्रा की सुविधा मिलेगी। श्री केदारनाथ धाम की तर्ज पर इंदौर से उज्जैन एवं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग तथा जबलपुर से चित्रकूट तथा ग्वालियर से ओरछा एवं

पीताम्बरा पीठ के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएँ प्रारंभ की जाएंगी। मुख्यमंत्री हेली पर्यटन सेवा योजना के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों के लिए पर्यटकों को हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री एयर एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ करते हुए प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों से गंभीर रूप से बीमार लोगों को एयरलिफ्ट कर बड़े अस्पतालों में शिफ्ट करने के लिए सर्वसुविधायुक्त एयर एम्बुलेंस चलाई जाएंगी। मध्यप्रदेश ऐसी एयर एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ करने वाला देश का अग्रणी राज्य बनेगा। अमृतकाल में प्रदेश की अर्थव्यवस्था, अध्यात्म और आरोग्य तीनों दृष्टि से एक नया अध्याय लिखेगी।

54. वन एवं पर्यावरण के संरक्षण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता ठीक उतनी ही है जितनी कि विकास के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के

कर-कमलों से कूनो राष्ट्रीय उद्यान में प्रारंभ हुई महत्वाकांक्षी चीता परियोजना सफल रही है। नववर्ष 2024 के प्रथम माह में ही यहाँ 7 चीता शावकों ने जन्म लिया है। राष्ट्रीय बाँस मिशन में अंतर्गत इस वर्ष 7 हजार 500 हेक्टेयर से भी अधिक क्षेत्र में बाँस रोपण कार्य कराया गया है। प्रधानमंत्री वन धन योजना के प्रथम चरण में 20 जिलों में 126 वन धन विकास केन्द्र क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। नदियों से प्राकृतिक रेत की निर्भरता को कम किया जाकर पत्थर से निर्मित रेत को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इंदौर नगर निगम द्वारा ग्रीन बांड के माध्यम से जलूद सोलर एनर्जी प्लांट का निर्माण, पर्यावरण की रक्षा में नागरिकों की भागीदारी का एक जीवंत उदाहरण है। साँची सोलर सिटी के बाद अब 5 प्रमुख पर्यटन शहरों को सोलर सिटी बनाने का लक्ष्य है। विश्व वेटलैंड दिवस 2024

की मेजबानी के अवसर पर तालाबों व जल स्रोतों के संरक्षण को जन-अभियान के रूप में संचालित करने का संकल्प सरकार ने लिया है।

55. प्रदेश के पत्रकारों के लिए विभिन्न सुविधाओं जैसे - सम्मान निधि, उपचार सहायता, आवास ऋण सहायता, स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा सहायता, शिक्षा ऋण एवं डिजिटल तकनीक प्रशिक्षण आदि का विस्तार किया गया है। विगत 1 वर्ष में मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के अंतर्गत पात्र अधिवक्ताओं एवं उनके आश्रितों को अनुदान सहायता के रूप में 6 करोड़ 75 लाख रुपए से अधिक की राशि प्रदान की गई है।

56. आकांक्षी विकासखण्ड कार्यक्रम प्रदेश के 29 जिलों के 42 विकासखण्डों में लागू किया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग के अनुसार प्रदेश के तिरला एवं पाटी

विकासखण्ड सेन्ट्रल जोन में क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर हैं।

57. माननीय प्रधानमंत्री जी की मिशन कर्मयोगी की अवधारणा को मेरी सरकार अक्षरशः लागू कर रही है। सोलहवीं विधानसभा के सभी निर्वाचित विधायकगण के लिए प्रबोधन कार्यक्रम तथा मंत्रिपरिषद के सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए लीडरशिप समिट का आयोजन किया गया है। अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी सतत आयोजित किए जा रहे हैं।

58. मेरी सरकार ने एक पल की भी विश्रांति लिए बिना प्रदेश की जनता की जिंदगी बदलने को ही ईश्वर की आराधना माना है। आइए, कर्तव्य काल में कर्तव्य पथ पर बढ़ते हुए हम सभी विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित मध्यप्रदेश को गढ़ने का संकल्प लें।

59. एक ऐसा मध्यप्रदेश, जो 'सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया' और "वसुधैव कुटुम्बकम्" के मंत्र के साथ विकास, सुशासन एवं जन-कल्याण में देश का नंबर वन राज्य बनेगा। एक ऐसा मध्यप्रदेश, जहाँ डबल इंजन की सरकार में गरीब, किसान, महिला एवं युवा सदैव प्राथमिकता के केंद्र-बिंदु रहेंगे। एक ऐसा मध्यप्रदेश, जो संस्कृति और प्रकृति के सान्निध्य में प्रगति की जय का उद्घोष बनेगा।

जय हिन्द - जय मध्यप्रदेश !

शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल–2024.